



Lakshya IAS

academy

18

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का विस्तार किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना, जिसे भारत के लिए जीवंत प्रधानमंत्री यशस्वी योजना



के नाम से जाना जाता है, का संचालन करता है। यह समग्र योजना अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें ४ उप-योजनाएं शामिल हैं: पूर्व-मैट्रिक, उत्तर-मैट्रिक, उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा और उत्कृष्ट महाविद्यालय शिक्षा। पात्र होने के लिए अभ्यर्थी की संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय २.५ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है।

मुख्य बिंदु:

- विस्तारित छात्रवृत्ति पहुंच: समग्र योजना पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के छात्रों को विद्यालय से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करती है।
- चार छात्रवृत्ति घटक: पात्र लाभार्थियों और छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक, उत्तर-मैट्रिक, उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा तथा उत्कृष्ट महाविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।
- वित्तीय बाधाओं में कमी: योजना का उद्देश्य वंचित छात्रों को वित्तीय कठिनाइयों के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने में सहायता करना तथा समान अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।

Government Expands PM-YASASVI Support for Educational Empowerment of OBC, EBC and DNT Students

The Ministry of Social Justice and Empowerment operates the PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India, known as PM-YASASVI. This umbrella scheme offers financial backing to students from Other Backward Classes, Economically Backward Classes, and De-notified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes. It comprises four sub-schemes: Pre-Matric, Post-Matric, Top Class School Education, and Top Class College Education. To qualify, the candidate's combined annual household income must not exceed 2.5 Lakh. Funding is disbursed straight to recipient accounts.



Key Points:

- Expanded scholarship access: The umbrella scheme supports eligible OBC, EBC and DNT students through scholarships spanning school and higher education.
- Four scholarship components: Support covers pre-matric, post-matric, top-class school education and top-class college education for eligible beneficiaries and students.
- Reducing financial barriers: The scheme aims to help disadvantaged students continue quality education without financial hardship and improve access to equal opportunities.

2. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छता

सेवाओं के मूल्यांकन के लिए स्वच्छ सेवा आकलन शुरू

✎ जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ सेवा आकलन शुरू किया। यह वार्षिक,



ग्राम पंचायत स्तर का डिजिटल स्व-मूल्यांकन ढांचा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत संचालित होता है। इसमें स्वच्छता सेवा वितरण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता तथा परिसंपत्तियों के समग्र संचालन और रखरखाव का मूल्यांकन किया जाता है। निष्कर्षों का ग्राम सभा द्वारा सत्यापन किया जाता है, जिससे स्थानीय निकाय कमियों की पहचान कर उच्च अधिकारियों को आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं और जमीनी स्तर पर सुधार योजनाएं तैयार कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

- डिजिटल स्वच्छता मूल्यांकन ढांचा: स्वच्छ सेवा आकलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण २.० के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता सेवा वितरण के मूल्यांकन के लिए वार्षिक ग्राम पंचायत स्तर का ढांचा है।
- समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली: ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता परिसंपत्तियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करती हैं।
- सत्यापन से सुधारात्मक कार्रवाई: मूल्यांकन निष्कर्षों का ग्राम सभा द्वारा सत्यापन किया जाता है, जिससे जिला और राज्य स्तर के अधिकारी सेवा संबंधी कमियों की पहचान कर सुधार योजनाएं तैयार कर सकते हैं।

Swachh Seva Aankalan Introduced to Assess Cleanliness Services under Swachh Bharat Mission Grameen

✎ The Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Jal Shakti



launched Swachh Seva Aankalan. This annual, Gram Panchayat level digital self assessment framework operates under Swachh Bharat Mission Grameen phase two. It evaluates sanitation service delivery, solid and liquid waste management, visual cleanliness, and overall asset operation and maintenance. Findings undergo Gram Sabha validation, empowering local bodies to identify gaps, submit data to higher authorities, and draft grassroot improvement plans.

Key Points:

- Digital sanitation assessment framework: Swachh Seva Aankalan is an annual Gram Panchayat-level framework for assessing rural sanitation service delivery under SBM-Grameen 2.0.
- Community-led monitoring system: Gram Panchayats, Gram Sabhas and Village Water and Sanitation Committees assess cleanliness, waste management and sanitation asset functionality.
- Validation drives corrective action: Assessment findings undergo Gram Sabha validation, enabling district and state authorities to identify service gaps and prepare improvement plans.

3. भारत और मर्कोसुर ने अधिमान्य व्यापार समझौते का विस्तार करने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए वार्ता शुरू की

भारत और मर्कोसुर व्यापार समूह ने अपने अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने इस निर्णय की घोषणा की, जिसमें उरुग्वे समूह की अस्थायी अध्यक्षता कर रहा है। दोनों पक्ष उत्पाद कवरेज और आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाने के लिए संदर्भ शर्तें निर्धारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्रों को अधिकृत करने के लिए पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया, जिससे कागजरहित व्यापार को बढ़ावा मिला और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं सरल हुईं।



मुख्य बिंदु:

- विस्तार वार्ता औपचारिक रूप से शुरू: भारत और मर्कोसुर ने अपने मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते को व्यापक बनाने और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए वार्ता शुरू की है।
- संदर्भ शर्तों की तैयारी: दोनों पक्ष प्रस्तावित विस्तारित समझौते के दायरे और संरचना को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें पारस्परिक रूप से पहचाने गए हित के क्षेत्र शामिल हैं।
- कागजरहित व्यापार प्रक्रियाएं: संबंधित प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्रों को सक्षम बनाता है, जिससे कागजरहित व्यापार को समर्थन मिलता है और मौजूदा समझौते के तहत सीमा शुल्क प्रक्रियाएं सरल होती हैं।

4. भारत ने संसदीय सहयोग को मजबूत करने के लिए केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न भारतीय राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के साथ कई संसद सदस्य शामिल थे। सम्मेलन के दौरान संस्थागत सहयोग को गहरा करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी विधायी नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं हुईं। हरिवंश को लोकतांत्रिक नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रमंडल देशों के भीतर संसदीय शासन को मजबूत करने पर महासभा को संबोधित करना था।



India and MERCOSUR Begin Talks to Broaden Preferential Trade Agreement and Strengthen Economic Cooperation

India and the MERCOSUR trade bloc formally launched negotiations to expand their Preferential Trade Agreement. Union Minister Piyush Goyal and Uruguay's Foreign Minister Mario Lubetkin announced the decision, with Uruguay holding the Pro Tempore Presidency of the group. Both sides are setting the Terms of Reference to broaden product coverage and economic ties. Additionally, they signed the First Additional Protocol to authorize electronic Certificates of Origin, advancing paperless trade and streamlining customs processes.



Key Points:

- Expansion negotiations formally launched: India and MERCOSUR have begun talks to broaden their existing Preferential Trade Agreement and deepen economic cooperation.
- Terms of reference preparation: Both sides are finalising the scope and structure of the proposed expanded agreement covering mutually identified areas of interest.
- Paperless trade procedures: A related protocol enables electronic Certificates of Origin, supporting paperless trade and simplifying customs procedures under the existing agreement.

4. India Participates in 69th Commonwealth Parliamentary Conference in Cape Town to Strengthen Parliamentary Cooperation

An Indian Parliamentary Delegation led by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh participated in the 69th Commonwealth Parliamentary Conference held in Cape Town. The delegation included several Members of Parliament alongside presiding officers and secretaries from various Indian state legislatures. During the conference, bilateral discussions took place with South African legislative leaders to deepen institutional cooperation. Harivansh was set to address the General Assembly on democratic leadership, international law, and strengthening parliamentary governance within Commonwealth nations.



मुख्य बिंदु:

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी: उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल १२ से १९ सितंबर तक केपटाउन में आयोजित सम्मेलन में भाग ले रहा है।
- द्विपक्षीय संसदीय सहभागिता: प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विचारों के आदान-प्रदान और दीर्घकालिक संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी संसदीय नेताओं के साथ चर्चा की।
- लोकतांत्रिक सहयोग पर ध्यान: सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों पर कार्यशालाएं और पूर्ण सत्र शामिल हैं, जिसमें भारत ने मजबूत लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून पर जोर दिया।

5. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर कारीगर पंजीकरण 30 लाख तक पहुंचा

- ✎ केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ने कार्यान्वयन के तीन वर्ष पूरे होने पर *० लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया। यह पहल बढ़ई, कुम्हार, लोहार और बुनकरों सहित १८ परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को व्यापक सहायता प्रदान करती है। पात्र कारीगरों को औपचारिक प्रमाणपत्र, प्रतिदिन ५०० की सहायता राशि के साथ बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण, १५००० तक के औजार प्रोत्साहन तथा ५ प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर * लाख तक के बिना किसी जमानत के उद्यम ऋण मिलते हैं।



मुख्य बिंदु:

- पंजीकरण लक्ष्य हासिल: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यान्वयन सहायता के तीन वर्ष पूरे होने के करीब *० लाख पंजीकृत लाभार्थियों के लक्ष्य तक पहुंच गई है।
- एकीकृत कारीगर सहायता: योजना पहचान, कौशल प्रशिक्षण, औजार प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन और विपणन सहायता को एक साथ जोड़ती है।
- प्रशिक्षण और ऋण में प्रगति: सितंबर के मध्य तक २४. *७ लाख से अधिक कारीगरों ने बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि ६.१९ लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए।

Key Points:

- Indian delegation participation: An Indian parliamentary delegation led by Deputy Chairman Harivansh is participating in the conference held in Cape Town from September 12 to 19.
- Bilateral parliamentary engagement: Delegation members held discussions with South African parliamentary leaders to exchange views and strengthen longstanding institutional relations.
- Democratic cooperation focus: The conference includes workshops and plenary discussions on contemporary parliamentary issues, with India highlighting stronger democracy and international law.

5. PM Vishwakarma Scheme Records 30 Lakh Artisan Registrations as It Completes Three Years

- ✎ The Central Sector Scheme PM Vishwakarma reached its target of registering 30 lakh beneficiaries upon completing three years of implementation. The initiative provides comprehensive support to artisans across 18 family-based traditional trades, including carpenters, potters, blacksmiths, and weavers. Eligible craftspeople receive formal certificates, basic and advanced skill training with a daily stipend of 500, toolkit incentives up to 15000, and collateral-free enterprise loans up to 3 lakh at a 5 percent concessional interest rate.



Key Points:

- Registration target achieved: PM Vishwakarma has reached 30 lakh registered beneficiaries as the scheme approaches three years of implementation support.
- Integrated artisan support: The scheme combines recognition, skill training, toolkit incentives, credit support, digital transaction incentives and marketing assistance.
- Training and credit progress: By mid-September, over 24.37 lakh artisans received basic training, while more than 6.19 lakh loans were sanctioned.

6. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा १५००० रुपये से बढ़ाकर २५००० रुपये प्रति माह की गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को १५००० रुपये से बढ़ाकर २५००० रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इस निर्णय से अनुमानित ५१ लाख अतिरिक्त श्रमिकों को सेवानिवृत्ति बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज सहित वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे। यह संशोधन बढ़ते वेतन स्तर और २०१४ में किए गए पिछले समायोजन के बाद औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है।



मुख्य बिंदु:

- उच्चतर कवरेज वेतन सीमा: मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को १५००० रुपये से बढ़ाकर २५००० रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी।
- विस्तारित श्रमिक कवरेज: संशोधन से लगभग ५१ लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत लाने की उम्मीद है।
- अतिरिक्त सरकारी व्यय: वैधानिक वेतन सीमा बढ़ने के बाद वार्षिक सरकारी व्यय में १,०८९ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है।

7. नीति आयोग ने राज्यों में विद्युत गतिशीलता परिवर्तन की तैयारी पर नजर रखने के लिए दूसरा भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक जारी किया

नीति आयोग ने भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक के दूसरे संस्करण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विद्युत गतिशीलता अपनाने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन करना है। सूचकांक १६ संकेतकों के आधार पर क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, जिन्हें * प्रमुख श्रेणियों में समूहित किया गया है: परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी और अनुसंधान एवं नवाचार। दिल्ली ने १०० में से ८४ अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक रहे। यह ढांचा राज्य स्तर पर तुलना, कमियों की पहचान और प्रतिस्पर्धी नीतिगत विकास को प्रोत्साहित करता है।



EPFO Wage Ceiling Raised from Rs. 15,000 to Rs. 25,000 per Month Following Cabinet Approval

The Union Cabinet approved the enhancement of the mandatory wage ceiling for coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15000 rupees to 25000 rupees per month. This decision will extend statutory social security benefits, including retirement savings, pension protection under EPS, and insurance coverage under EDLI, to an estimated 51 lakh additional workers. The revision reflects rising wage levels and expansion in formal employment since the last adjustment made in 2014.



Key Points:

- Higher coverage wage ceiling: The Cabinet approved raising the EPFO mandatory coverage wage ceiling from Rs. 15,000 to Rs. 25,000 monthly.
- Expanded worker coverage: The revision is expected to bring about 51 lakh additional employees under EPFO social security coverage.
- Additional government expenditure: Annual government expenditure is projected to increase by Rs. 1,089 crore following the higher statutory wage ceiling.

NITI Aayog Releases Second India Electric Mobility Index to Track State-Level EV Transition Readiness

NITI Aayog launched the second edition of the India Electric Mobility Index to assess state and Union Territory level progress in adopting electric mobility. The index scores regions across sixteen indicators grouped into three primary categories: transport electrification, charging infrastructure readiness, and research and innovation. Delhi secured the top rank with a score of 84 out of 100, followed by Maharashtra and Karnataka. The framework encourages state-level benchmarking, gap identification, and competitive policy developments.



मुख्य बिंदु:

- दूसरे सूचकांक संस्करण की शुरुआत: नीति आयोग ने विद्युत गतिशीलता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन करने के लिए भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक २०२५ जारी किया।
- १६ संकेतकों पर नजर: सूचकांक परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी और अनुसंधान एवं नवाचार से संबंधित संकेतकों के माध्यम से विद्युत गतिशीलता का मूल्यांकन करता है।
- नीतिगत तुलना को मजबूत करना: सूचकांक राज्यों को प्रगति की तुलना करने, कमियों की पहचान करने और कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करने में सहायता करता है तथा मजबूत विद्युत गतिशीलता नीतिगत कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।

8. जी२० ऊर्जा बैठक में ऊर्जा प्रचुरता और सतत ऊर्जा प्राथमिकताओं पर वैश्विक सहयोग को प्रमुखता दी गई

- ✎ केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित जी२० ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सत्रों के दौरान भारत ने एक लचीली और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की दिशा में अपनी प्रगति पर प्रकाश डाला तथा बताया कि स्थापित क्षमता ५५२ गीगावाट से अधिक है, जिसमें गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी ५० प्रतिशत से अधिक है। चर्चाओं में * प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया: ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती आधारभूत ऊर्जा, अनुमति एवं नियामक दक्षता तथा गैर-जीवाश्म क्षमता विस्तार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, जिसमें २०*० तक ५०० गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता हासिल करना शामिल है।



मुख्य बिंदु:

- वैश्विक ऊर्जा चर्चाएं: जी२० ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य, अवसंरचना विकास और लचीली ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा की गई।
- चर्चा के * स्तंभ: मंत्रिस्तरीय सत्रों में सस्ती आधारभूत ऊर्जा, नियामक दक्षता और भाग लेने वाले देशों के लिए लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Key Points:

- Second index edition launched: NITI Aayog launched the India Electric Mobility Index 2025 to assess state and union territory progress in electric mobility.
- Sixteen indicators tracked: The index evaluates electric mobility through indicators covering transport electrification, charging infrastructure readiness, and research and innovation.
- Policy benchmarking strengthened: The index helps states compare progress, identify gaps and exchange practices while encouraging stronger electric mobility policy action.

8. G20 Energy Meeting Highlights Global Cooperation on Energy Abundance and Sustainable Energy Priorities

- ✎ Union Minister of Power Manohar Lal represented India at the G20 Energy Abundance Ministerial Meeting in Houston, United States. During the sessions, India highlighted its progress toward building a resilient, future-ready energy system, noting an installed capacity of over 552 GW with non-fossil sources accounting for over 50 percent. The discussions focused on three key pillars: energy security and affordable baseload, permitting and regulatory efficiency, and building resilient critical-mineral supply chains while advancing non-fossil capacity expansion goals like reaching 500 GW of non-fossil power capacity by 2030.



Key Points:

- Global energy discussions: The G20 Energy Abundance Ministerial Meeting addresses energy security, affordability, infrastructure development and resilient energy supply chains.
- Three discussion pillars: Ministerial sessions focus on affordable baseload energy, regulatory efficiency, and resilient critical-mineral supply chains for participating countries.

- भारत की भागीदारी की प्राथमिकताएं: भारत ने लचीली ऊर्जा प्रणालियों, विविधीकृत महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला।

9. जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी स्प्राउट सुविधा का उद्घाटन

- ✎ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित बीआरआईसी-राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी स्प्राउट सुविधा का उद्घाटन



किया। स्पीडसीड फीनोटाइपिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूनिफाइड ट्रेट एनालिसिस के लिए प्रयुक्त स्प्राउट एक नियंत्रित पर्यावरण प्रणाली है, जिसे उच्च-प्रवाह फीनोटाइपिंग और सटीक तनाव जांच के लिए तैयार किया गया है। यह जीनोमिक्स और गुण मूल्यांकन के बीच समन्वय स्थापित करके चने जैसी जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों के विकास को तेज करता है। यह पहल कृषि लचीलापन और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की बायोई* नीति के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु:

- जलवायु अनुसंधान सुविधा: स्प्राउट सुविधा का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली फसल किस्मों के विकास के लिए उन्नत अनुसंधान को समर्थन देना है।
- त्वरित फसल विकास: यह सुविधा नियंत्रित पर्यावरणीय अध्ययनों को सक्षम बनाती है, जिससे शोधकर्ता तापमान, जल उपलब्धता और जलवायु संबंधी अन्य तनावों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं।
- कृषि लचीलेपन पर ध्यान: स्प्राउट जलवायु परिवर्तनशीलता के बीच उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि को समर्थन देने वाली लचीली फसलों के विकास की भारत की क्षमता को मजबूत करता है।

9. Indigenous SPROUT Facility Inaugurated to Advance Development of Climate-Resilient Crop Varieties

- ✎ Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated the indigenous SPROUT facility at BRIC-National



Institute of Plant Genome Research in New Delhi. Standing for SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis, SPROUT is a controlled-environment system designed for high-throughput phenotyping and precision stress screening. It accelerates the development of climate-resilient crop varieties like chickpea by bridging genomics and trait evaluation. This initiative aligns with India's BioE3 policy to enhance agricultural resilience and food security.

Key Points:

- Climate research facility: The SPROUT facility supports advanced research aimed at developing crop varieties capable of performing under changing climatic conditions.
- Accelerated crop development: The facility enables controlled environmental studies, helping researchers evaluate plant responses to temperature, water availability and other climate-related stresses.
- Agricultural resilience focus: SPROUT strengthens India's capacity to develop resilient crops that can support productivity, food security and sustainable agriculture amid climate variability.

10. रक्षा विनिर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा डीप-टेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए डीआरडीओ ने नई उद्योग साझेदारी पहल का अनावरण किया

नई दिल्ली में आयोजित विमर्श डीआरडीओ-उद्योग समन्वय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विनिर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा डीप-टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए नई नीतिगत पहलों की घोषणा की। इन उपायों के तहत, डीआरडीओ ने उन्नत विनिर्माण मूल्यांकन और रेटिंग प्रणाली, संस्करण २.० के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस ढांचे का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े वर्गों में घरेलू रक्षा उद्यमों की विनिर्माण परिपक्वता का मानकीकरण और मूल्यांकन करना तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।



मुख्य बिंदु:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रवेश की बाधाएं कम: डीआरडीओ ने वित्त पोषण, इनक्यूबेशन सहायता और परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले उपाय शुरू किए, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा डीप-टेक रक्षा स्टार्टअप को सहायता मिलेगी।
- सुरक्षित सॉफ्टवेयर ढांचा: लाइसेंसधारी उद्योगों के साथ डीआरडीओ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड साझा करने के लिए एक ढांचा सॉफ्टवेयर-आधारित रक्षा क्षमताओं और अप्रचलन प्रबंधन को समर्थन देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विस्तार: उन्नत रक्षा प्रणालियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए १* विनिर्माण भागीदारों को ९ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंसिंग समझौते सौंपे गए।

— ★ ★ ★ —

10. DRDO Unveils New Industry Partnership Measures to Support MSMEs and Deep-Tech Start-ups in Defence Manufacturing

During the VIMARSH DRDO-Industry Synergy Meet held in New Delhi, Defence Minister Rajnath Singh announced new policy initiatives to empower MSMEs and deep-tech start-ups in defence manufacturing. As part of these measures, DRDO signed a contract with the Quality Council of India for the System for Advance Manufacturing Assessment and Rating, version 2.0. This framework aims to benchmark and assess the manufacturing maturity of domestic defence enterprises across micro, small, medium, and large categories to enhance competitiveness.



Key Points:

- MSME entry barriers reduced: DRDO introduced measures offering funding, incubation support and access to testing facilities for MSMEs and deep-tech defence startups.
- Secure software framework: A framework for sharing DRDO-developed software source codes with licensee industries aims to support software-defined defence capabilities and obsolescence management.
- Technology transfer expanded: Nine technology transfer licensing agreements were handed over to 13 manufacturing partners for commercial production of advanced defence systems.

— ★ ★ ★ —

दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. सितंबर 2026 में डीआरडीओ-उद्योग बैठक के दौरान डीआरडीओ ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ किस अद्यतन मूल्यांकन ढांचे के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए?

- (a) समार 2.0
- (b) जेड 2.0
- (c) रक्षा-गुणवत्ता 2026
- (d) आईएसओ रक्षा 9001

Q2. सितंबर 2026 में बीआरआईसी-एनआईपीजीआर में उच्च-प्रवाह फीनोटाइपिंग के माध्यम से जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों के विकास को तेज करने के लिए उद्घाटित स्वदेशी अत्याधुनिक सुविधा का नाम क्या है?

- (a) एग्री-सीड
- (b) फीनो-प्लांट
- (c) क्रॉप-टेक
- (d) स्प्राउट

Q3. सितंबर 2026 की जी20 ऊर्जा बैठक के दौरान भारत द्वारा दोहराया गया कौन-सा प्रमुख वैश्विक लक्ष्य 2030 के लिए नवीकरणीय क्षमता लक्ष्यों को निर्धारित करता है?

- (a) 1000 गीगावाट
- (b) 300 गीगावाट
- (c) 750 गीगावाट
- (d) 500 गीगावाट

Q4. सितंबर 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक के दूसरे संस्करण में किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया?

- (a) महाराष्ट्र
- (b) दिल्ली
- (c) कर्नाटक
- (d) तमिलनाडु

Q5. सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि करने की मंजूरी दी?

- (a) 18,000 रुपये
- (b) 20,000 रुपये
- (c) 25,000 रुपये

Q1. During the DRDO-Industry meet in September 2026, DRDO signed a contract with the Quality Council of India for which updated assessment framework?

- (a) SAMAR 2.0
- (b) ZED 2.0
- (c) DEF-QUAL 2026
- (d) ISO Defence 9001

Q2. What is the name of the indigenous, state-of-the-art facility inaugurated at BRIC-NIPGR in September 2026 to accelerate the development of climate-resilient crop varieties through high-throughput phenotyping?

- (a) AGRI-SEED
- (b) PHENO-PLANT
- (c) CROP-TECH
- (d) SPROUT

Q3. What key global target reiterated by India during the September 2026 G20 Energy Meeting outlines renewable capacity goals for 2030?

- (a) 1000 GW
- (b) 300 GW
- (c) 750 GW
- (d) 500 GW

Q4. In September 2026, which state/UT achieved the top rank in the 2nd edition of the India Electric Mobility Index (IEMI) released by NITI Aayog?

- (a) Maharashtra
- (b) Delhi
- (c) Karnataka
- (d) Tamil Nadu

Q5. In September 2026, the Union Cabinet approved raising the monthly wage ceiling for mandatory Employees' Provident Fund (EPFO) coverage to what amount?

- (a) 18,000 rupees
- (b) 20,000 rupees
- (c) 25,000 rupees
- (d) 30,000 rupees

- (d) 30,000 रुपये
- Q6. सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बिना किसी जमानत के ऋण सहायता और कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने पारंपरिक व्यवसाय वर्ग या शिल्प शामिल हैं?
- (a) 12
(b) 15
(c) 24
(d) 18
- Q7. सितंबर 2026 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया?
- (a) ओम बिरला
(b) जगदीप धनखड़
(c) हरिवंश नारायण सिंह
(d) पीयूष गोयल
- Q8. सितंबर 2026 में भारत के साथ व्यापार विस्तार वार्ता के दौरान मर्कोसुर की अस्थायी अध्यक्षता की मेजबानी किस देश ने की?
- (a) अर्जेंटीना
(b) उरुग्वे
(c) ब्राज़ील
(d) पैराग्वे
- Q9. सितंबर 2026 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सेवाओं के मूल्यांकन के लिए कौन-सी पोर्टल आधारित पहल शुरू की गई?
- (a) स्वच्छ सेवा आकलन
(b) स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण
(c) ग्राम स्वच्छता रेटिंग
(d) निर्मल ग्राम प्रहरी
- Q10. 2026 में अद्यतन प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित पात्र छात्रों के लिए अधिकतम वार्षिक अभिभावकीय आय सीमा कितनी है?
- (a) 1.5 लाख
(b) 2.5 लाख
(c) 4.0 लाख
(d) 8.0 लाख

- Q6. How many traditional trade categories/crafts are covered for collateral-free credit support and skill training under the PM Vishwakarma Scheme as of September 2026?
- (a) 12
(b) 15
(c) 24
(d) 18
- Q7. Who led the Indian Parliamentary Delegation at the 69th Commonwealth Parliamentary Conference (CPC) held in Cape Town, South Africa, in September 2026?
- (a) Om Birla
(b) Jagdeep Dhankhar
(c) Harivansh Narayan Singh
(d) Piyush Goyal
- Q8. Which country served as the pro-tempore presidency host of MERCOSUR during the trade expansion talks with India in September 2026?
- (a) Argentina
(b) Uruguay
(c) Brazil
(d) Paraguay
- Q9. In September 2026, which portal-based initiative was introduced under Swachh Bharat Mission (Grameen) to evaluate cleanliness services across rural Gram Panchayats?
- (a) Swachh Seva Aankalan
(b) Swachh Sarvekshan Rural
(c) Gram Swachhta Rating
(d) Nirmal Gram Pahar
- Q10. Under the PM-YASASVI scheme guidelines updated in 2026, what is the maximum annual parental income limit for eligible students belonging to Other Backward Classes (OBC)?
- (a) 1.5 Lakh
(b) 2.5 Lakh
(c) 4.0 Lakh
(d) 8.0 Lakh

उत्तरमाला (Answer Key)

1 A 2 D 3 D 4 B 5 C 6 D 7 C 8 B 9 A 10 B

